युवा राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

–डॉ. गायत्री शर्मा
सहायक प्राध्यापक (हिंदी)
चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़,
इंदौर (म.प्र.)
ई–मेल : charkli01@gmail.com
मोबा. नं. 98278 82950

बीज शब्द–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय संस्कृति, भारतीय युवा

विषय परिचय :

शिक्षा व समाज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षित समाज ही देश के विकास का द्योतक है। समाज व शिक्षा के अन्योन्याश्रित संबंधों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सरोकारों पर केंद्रित शिक्षा पद्धति देश के विकास में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। शैक्षिक नवाचार के रूप में भारत में लागू की गई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020', इक्कीसवीं सदी के बदलते भारत की वो उजली तस्वीर है, जिसमें देश के विश्वगुरू बनने का स्वप्न पुनः साकार होता दिखाई देता है। युगानुरूप परिवर्तनों को समाविष्ट कर नवीन कलेवर में प्रस्तुत 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षा प्रणाली व नवीन तकनीकी शिक्षा प्रणाली का वो बेहतरीन समायोजन है, जिसका केंद्रीय लक्ष्य भारतीय युवाओं को शिक्षित बनाने के साथ ही उन्हें सभ्य, संस्कारवान, जागरूक, आत्मनिर्भर व कौशल संपन्न नागरिक बनाना भी है।

शिक्षा की सरलता, सुलभता व सार्वभौमिकता को केंद्र में रखकर विकसित भारत के नवरूप को परिलक्षित करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (एनईपी 2020) विकास के पथ पर कदमताल करते भारत के भविष्य की वो नई इबारत है, जिसका लक्ष्य देश के युवाओं को भारत की समद्ध शिक्षण परंपरा, कला, धर्म, संस्कृति व विरासत परीचित कराना तथा शिक्षा के प्रति अधिकाधिक छात्रों की रूचि जागृत करना है। शिक्षा व संस्कार देश की प्रगति की गाड़ी के वो दो पहिये है, जिनका पारस्परिक समायोजन ही देश के उत्थान और पतन में निर्णायक भूमिका अदा करता है। किसी भी परिवार व देश के भविष्य का निर्धारक युवा होता है। शिक्षा यदि किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहे तो वह कभी सामाजिक सरोकारों व नैतिक मूल्यों से युवाओं को नहीं जोड़ पाएगी। शिक्षा को युवाओं के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसे तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान के तालमेल के उस ताने–बाने से जोड़ना होगा, जिसका मूल मंतव्य युवाओं को शिक्षित करने के साथ ही चरित्रवान, संस्कारवान व गुणवान बनाना होगा, जिससे कि वह युवा अपने परिवार के उत्थान के साथ ही राष्ट्रनिर्माण में भी अपना योगदान दे सके।

किसी भी देश के पिछड़ेपन के प्रमुख दो कारण गरीबी व अशिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक व मानसिक रूप से एक मजबूत आधार प्रदान करती है। देश का युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी

नहीं होगा। राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की सहभागिता को दृष्टिगत रखकर 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को इस मंतव्य से तैयार किया गया है, जिससे कि छात्रों की रूचि बाल्यकाल से ही शिक्षा के प्रति जागृत हो सके और उन्हें पढ़ाई कभी उबाऊ या बोझ न लगे। शिक्षा में नवोन्मेष के साथ प्रकाश में आई कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित 'एनईपी 2020' छात्रों को तकनीकी शिक्षा व व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही ऐसे अनेक विषयों से भी परीचित कराती है, जो उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत, सुखद वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य के लक्ष्य से जोड़ते हैं।

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति :

प्राचीनकाल में 'विश्व गुरू' के रूप मे दुनिया का सिरमौर बना भारत अपनी गुरूकुल परंपरा के कारण दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाता था। यह शिक्षा के विश्वगुरूओं की वह उर्वर भूमि है, जिस पर वाल्मीकि, सांदीपनि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण परंहस, स्वामी विवेकानंद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आदि अनेक ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक हुए है, जिनकी ख्याति दुनियाभर में फैली थी। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति इसलिए भी कारगर कही जाती थी क्योंकि उस काल में शिक्षा किताबों पर कम और व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होती थी। प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी आदि विश्वविद्यालयों का नाम दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता था, इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए विदेशों से छात्र भारत आते थे।

भारतीय भाषाओं को मिलेगा सम्मान :

समय बदलने के साथ–साथ भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में भी कई परिवर्तन हुए। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति में कई ऐसे परिवर्तन किए गए, जिससे कि युवा भारत की कला, सभ्यता व संस्कृति से परीचित हो सके। कहने तो भारत वर्ष 1947 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था लेकिन यह अंग्रेजों की गुलामी की यादों की छाप ही है कि धरा पर तन से तो हम आजाद हो गए पर मन से अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही है। अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलते हुए आज भारतीय छात्र भी अंग्रेजीयत के गुमान में इठलाने लगे है और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से किनारा करने लगे हैं। वाचिक व लेखिक तौर पर हिंदी का प्रयोग करना युवाओं के लिए अब सम्मान नहीं बल्कि अशिक्षा या अल्पशिक्षा की पहचान बन गया है। आज के युवा हिंदी व अपनी क्षेत्रीय भाषायी पहचान पर शर्म करने लगे है। इसी शर्म को सम्मान में बदलने का बीड़ा भारत की नई शिक्षा नीति ने उठाया है। भारत की राष्ट्रभाषा व प्रादेशिक भाषाओं के उत्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का योगदान महत्वपूर्ण है।

एक देश, एक शिक्षा प्रणाली :

भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देश में विगत कई वर्षों में सरकारी शिक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम के प्रति छात्रों का रूझान बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा था, जिसका प्रमुख कारण भारतीय शिक्षा नीति का समय की मांग के

अनुसार नहीं बदलना था। अब छात्र स्कूली पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में और उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों या विदेशों में जाने में अधिक रूचि लेने लगे थे। यही कारण है कि समयानुरूप बदलावों के साथ नवीनतम स्वरूप में 'एनईपी 2020' ने अपने प्राथमिक लक्ष्य के तौर पर छात्रों को तकनीकी, व्यवहारिक व धर्म–संस्कृति के ज्ञान के परीचित कराने के साथ ही उनके व्यक्तित्व के विकास करने की दिशा में नव परिवर्तनों का आगाज़ किया और 'एक देश, एक शिक्षा नीति' का लक्ष्य रखा। जिसके फलस्वरूप नवीनतम पाठ्यक्रम के रूप में छात्रों को विषय चयन की आजादी के साथ ही बहुद्वार आगम और बहुद्वार निर्गम का विकल्प भी दिया गया।

इस नीति के केंद्र में जहां एक ओर छात्र थे, वहीं दूसरी ओर शिक्षक भी थे, जिन्हें एनईपी 2020 के रूप में शिक्षा के नवयुग की मांग के अनुरूप सबल बनाने के लिए शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स व कई सर्टिफिकेशन कोर्स भी आरंभ किए गए। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि एनईपी के लागू होने के बाद छात्र और शिक्षक दोनों ही ज्ञान व तकनीकसंपन्न बनने की दिशा में अग्रसर है।

भारत में लागू की गई शिक्षा नीतियां :
भारत में गांधी सत्तात्मक काल में वर्ष1968 में पहली एवं वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिनमें शिक्षा पद्धति में समयानुरूप यथासंभव सुधार तो किए गए लेकिन फिर भी कई परिवर्तनों के बाद भी वे शिक्षा पद्धति भारतीय छात्रों की मानसिकता व रूचि की कसौटी पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती थी। यही कारण है कि अब तक देश के युवाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के सरकार के सभी प्रयास 'ऊंट के मुंह में जीरे के समान' अल्प ही साबित हुए है। देश के विकास मे शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए वर्ष 2009 में 'शिक्षा के अधिकार' को भारत के कानून में संविधानिक मान्यता दी गई लेकिन इसके बाद भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का यह प्रलोभन अधिकाधिक संख्या में भारतीय छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाया, जिसके पीछे मुख्य वजह गरीबी, पिछड़ापन व शिक्षा का रोजगारोन्मुखी न होना था। बीते कुछ वर्षों में भारतीय छात्रों का शिक्षा व रोजगार के लिए विदेशों में पलायन भी सरकार के लिए एक चिंतनीय प्रश्न बन गया था, जिसके समाधान की उपज 'एनईपी2020'है।

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् माता और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। मां जो हमें जन्म देने के साथ ही हममें संस्कारों का बीज भी रोपित करती है। मां की भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है, जिसे हम सबसे पहले सीखते है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के बाद हमारे जीवन की प्रथम गुरू की यह शिक्षा स्कूली शिक्षा के बोझ तले इतनी कमजोर पड़ जाती है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते हम अपनी मातृभाषा से दूर हो जाते है और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में धीरे–धीरे हम अपनी संस्कृति और संस्कारों की सुवास को भी विस्मृत कर देते है। यह शिक्षासंपन्न होने के साथ–साथ धनसंपन्न होने की हमारी अति महात्वाकांक्षा व लालसा ही है, जिसके चलते अब हम अपने गांव, अपने राज्य और अपने देश से दूर–दूर होते–होते विदेशों में पलायन के स्वप्न भी देखने लगे है। आप ही सोचिएं कि पश्चिमी सभ्यता के मोहपाश की चमक में

अब कहां गुम हो गई हमारी वो मां और कहां गुम हो गया हमारा वो मातृभूमि प्रेम, जो कभी हमें स्वर्ग से भी बढ़कर सुखद शीतलता प्रदान करता था?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम

पिछले कुछ दशकों में भारत में शिक्षा ज्ञानार्जन का साधन कम और प्रतिस्पर्धा के दौर में महंगे दामों में बिकने वाली एक वस्तु बन चुकी थी, जिसका व्यापार चरम उत्कर्ष पर था। शिक्षा के व्यापार पर नकेल कसने, उसके गिरते स्तर को बचाने, शिक्षा छोड़ चुके छात्रों को शिक्षा से जोड़ने व शिक्षकों के सम्मान को पुर्नजीवित करने के लिए देश में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू की गई। इस नवीनतम शिक्षा नीति में विद्यालय व महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कई ऐसे नवीनतम विषयों व गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करने के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए 'एनईपी 2020'के पाठ्यक्रम में शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं व भारत की कला, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण तथा इतिहास से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर इस शिक्षा को छात्रों के उम्रानुरूप मानसिक स्तर के आधार पर तैयार किया गया है। पुराने (10+2) के स्थान पर नवीनतम शिक्षा नीति का (5+3+3+4) मॉडल भारत में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती खेब को कौशल व रोजगार से जोड़ने के साथ ही उन्हें एक सभ्य, शिक्षित, कौशलसंपन्न, जागरूक, आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तनों का जनक होगा, जिसके भविष्यगामी परिणाम निश्चित तौर पर सुखद होंगे।

भारत क्या है? यहां की कला, संस्कृति, धर्म, सभ्यता आदि का क्या महत्व है? इससे अनभिज्ञ छात्रों के लिए नवीन शिक्षा नीति उस मजबूत ढ़ाचे की तरह डिजाइन की गई है, जिसकों गहराई से जानने व समझने के बाद यह समझना आसान हो जाएगा कि आखिर क्यों भारत को शिक्षा, धर्म व संस्कृति की दृष्टि से दुनिया का सिरमौर कहा जाता था। कोरोना के कठिन दौर में जब दुनिया में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, ऐसे में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को भारतीय युवाओं की दिमागी क्षमता व देश में हो रहे निरंतर अनुसंधान कार्यों का परिचय दे दिया था। इसी प्रकार चांद की सतह पर पहुंचकर 'इसरो' ने दुनिया को फिर से दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। पग–पग पर कामयाबी के परचम लहराता यह वो आत्मनिर्भर भारत है, जिसने 'मेक इन इंडिया' मिशन के सहारे कोरोना की कठिन जंग को भी आत्मविश्वास के साथ जीता था और दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत के युवाओं की दिमागी व शारीरिक क्षमताएं असीमित है। भारतीय छात्रों की सीखने की क्षमता को दृष्टिगत रखकर बनाई गई 'एनईपी 2020' निकट भविष्य में दुनिया का `भारतीय छात्रों के ज्ञान, कौशल, शोध व अनुसंधान की क्षमताओं के नवीनतम चमत्कारों से परीचित कराने की दिशा में वो नींव का पत्थर सिद्ध होगी, जिसका अनुसरण निकट भविष्य में दुनिया के अन्य देश भी करेंगे।

उपसंहार :

शिक्षा को सीमित विषयों के दायरों से मुक्त कर रूचिपूर्ण विषयों के दायरे में लाने में 'एनईपी 2020' की महती भूमिका है। छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस शिक्षा नीति में बहुद्वार आगम व बहुद्वार निर्गम की सुविधा से शिक्षण प्रणाली में लचीलापन व सुगमता लाने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 'एक देश, एक शिक्षा नीति' के मॉडल पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भारतीय छात्रों अपितु विदेशी छात्रों व विश्वविद्यालयों को भी भारत की ओर आकर्षित करने में व भारतीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण करने में कामयाब सिद्ध होगी।

संदर्भ–

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

https://spmrf.org/the-dream-of-a-self-reliant-india-can-be-realized-the-new-national-education-policy-2020/

https://www.entab.in/importance-and-benefits-of-the-national-education-policy.html

https://bpspbedcollege.in/wp-content/uploads/2020/05/NPE-1986.pdf